पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र योजना

Revamped Distribution Sector Scheme (RDSS)

➢ पृष्ठभूमिः–

केन्द्र सरकार द्वारा पुनरोत्थान वितरण क्षेत्र योजना (RDSS) का शुभारम्भ 20, जुलाई 2021 को हुआ था, जिसकी पूर्णता अवधि पूर्व में मार्च, 2026 थी, विद्युत मंत्रालय के ज्ञापांक F.No.20/9/ 2019-IPDS/ E-248708 दिनांक 16.07.2025 द्वारा मार्च, 2028 तक बढा दी गई है। जिसकी स्वीकृति दिनांक 18, जुलाई–2022 को प्राप्त हुई है।

24X7 निर्वाध गुणवत्तायुक्त, विश्वसनीय, सस्ती बिजली प्रदान करने के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई है। इस योजना का उददेश्य वितरण क्षेत्र में कुशल वित्तीय स्थिरता और परिचालन के माध्यम से बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और सामर्थ्य में सुधार करना है। यह एक सुधार आधारित और परिणाम से जुड़ी समयबद्ध योजना है। इस योजना में वितरण क्षेत्र के बुनियादीढ़ांचा को मजबूत करना और इसके लिये वितरण कम्पनी को सशक्त एवं दीर्घकालीन वित्तीय सहायता के प्राविधानों से सुधार करना है। यह वित्तीय सहायता पूर्व अर्हता मापदण्डों को पूरा करने और बुनियादी न्यूनतम बैंचमार्क की उपलब्धि पर आधारित है।

योजना का उद्देश्यः–

योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार है–

- विद्युत वितरण क्षेत्र में वित्तीय रूप से स्थायी और परिचालन रूप से कुशल वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और सामर्थ्य में सुधार करना।
- वर्ष 2024–25 तक AT&C हानियों को अखिल भारतीय स्तर पर 12% -15% के स्तर तक कम करना।
- वर्ष 2024–25 तक ACS-ARR के अन्तराल को कम करके शून्य करना।

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR):-

राज्य के समस्त जनपदो/मण्डलो हेतु केन्द्र की एजेंसी मै0 पी0एफ0सी0 एवं विद्युत मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की निगरानी समिति (Monitoring Committee) द्वारा वर्तमान तक Smart Metering एवं Distribution Infrastructure Works के सब घटक Loss Reduction Works के अन्तर्गत अब तक कुल ₹ 2336.24 करोड़ की विभिन्न परियोनाओं को स्वीकृतियाँ प्रदान की गई हैं।

योजना के लाभ (Benefits of Scheme):

- ❖ योजना की एक प्रमुख विशेषता Smart Metering को सार्वजनिक–निजी–साझेदारी (PPP) मोड में लागू कर उपभोक्ता सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। Smart Meter उपभोक्ताओं को मासिक आधार के बजाय नियमित आधार पर अपनी बिजली की खपत की निगरानी की सुविधा देगा जो उन्हें अपनी जरूरतों के अनुसार और उपलब्ध संसाधनों के सन्दर्भ में बिजली के उपयोग में मदद कर सकेगा।
- ❖ स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को उन अवसरों की पहचान करने में मदद करता है जहाँ वे ऊर्जा बचत कर सकते है और कुल बिजली खपत को कम कर सकते है।

क्रमशः.....2

- ❖ प्रत्येक माह बिना मीटर रीडर की आवश्यकता के सही व सटीक बिल की मोबाइल फोन पर उपलब्धता होगी।
- ❖ बिजली की हो रही खपत की लगभग रियल टाइम में जानकारी प्रत्येक समय मोबाइल एप के माध्यम से उपलब्ध रहेगी।
- ❖ मोबाइल एप व उ0पा0का0लि0 वेबसाइट पर उपलब्ध डिजीटल माध्यमों से 24X7 भुगतान की सुविधा।
- ❖ उपभोक्ता द्वारा Roop-top सोलर लगाए जाने पर स्मार्ट मीटर को ही नेट–मीटर के रूप मे प्रयोग में लाया जा सकेगा। चिन्हित ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण होने के उपरान्त सम्बन्धित क्षेत्रों में निर्वाध, गुणवत्तायुक्त, विश्वसनीय, विद्युत आपूर्त्ति के साथ–साथ विद्युत हानियों में कमी आयेगी।
- ❖ सुरक्षा के दृष्टिगत एल0टी0 ABC Conductor के कार्यों के उपरान्त विद्युत दुर्घटनाओं की सम्भावना में कमी के साथ–साथ बिजली चोरी को भी रोका जा सकेगा, जिससे वितरण कम्पनी के राजस्व में वृद्धि होगी।
- ❖ विद्युत लाईनों में Covered Conductor की स्थापना से विद्युत व्यवधानों में व्यापक कमी आयेगी एवं विद्युत दुर्घटनाओं में भी कमी परिलक्षित होगी।

➢ **योजना के अन्तर्गत निम्न मुख्य कार्य प्रस्तावित हैं:–**

- ❖ 15.84 लाख उपभोक्ताओं के परिसर में स्मार्ट मीटर की स्थापना का कार्य।
- ❖ 2602 नग फीडर स्मार्ट मीटर की स्थापना का कार्य।
- ❖ 59212 नग वितरण परिवर्तकों स्मार्ट मीटर की स्थापना का कार्य।
- ❖ 3334 नग एच0टी0 उपभोक्ताओं में स्मार्ट मीटर की स्थापना का कार्य।
- ❖ 4837 किमी LT केबिल को AB केबिल से बदलने का कार्य।
- ❖ 10 नग कृषि तथा अतिभारित 11 के0वी0 फीडरों का पृथक्कीकरण का कार्य।
- ❖ 469 नग DTR Structure तथा 8828 नग क्षतिग्रस्त पोलों को बदलने का कार्य।
- ❖ Supply Reliability बढाए जाने के उद्देश्य से फीडरों की Inter-linking का कार्य।
- ❖ Old-VCB Replacement का कार्य।
- ❖ Border Out Post एवं Vibrant Village Program के अन्तर्गत कुल 04 नग 33/11 के0वी0 नये सबस्टेशन का निर्माण कार्य सहित उनको ग्रिड के माध्यम से विद्युतीकरण का कार्य।

क्रमशः.....3

- ❖ गंगा कोरिडोर के अन्तर्गत 02 नं0 नये 33/11 के0वी0 सबस्टेशन तथा कुल 74.82 कि0मी0 33 के0वी0 एवं 178.83 कि0मी0 11 के0वी0 लाइन तथा 157.70 कि0मी0 एल0टी0 लाइन का भूमिगत का कार्य जाना है।
- ❖ गंगा कोरिडोर के अन्तर्गत कुल 18.50 कि0मी0 एल0टी0 AB Cable एवं 73 नग नये CSS लगाये जाने का कार्य किया जाना है।
- ❖ बेहतर उपभोक्ता सेवा तथा संतुष्टि के दृष्टिगत IT संरचना के सुदृढ़ीकरण का कार्य।

➢ स्मार्ट मीटरिंग के कार्य हेतु लक्ष्यः

Sl. No.	Meter Type	Quantity in Nos.
1	Single Phase Whole Current Consumer Meter	1478084
2	Three Phase Whole Current Consumer Meter	99014
3	Three Phase LTCT Consumer Meter	7438
4	Three Phase HTCT Consumer Meter	3334
5	DT Meter	59212
6	Feeder Meter	2602
	Total	**1649684**

➢ स्मार्ट मीटरिंग हेतु वित्तीय स्वीकृतिः

- दिनांक 05–08–2024 को स्मार्ट मीटरिंग हेतु ₹ 54.80 करोड़ की अतिरिक्त स्वीकृति प्रदान की गई, जिसके पश्चात स्मार्ट मीटरिंग कार्य कुल परिव्यय रू0 1099.84 करोड़ की हो गया है। जिसका विवरण निम्न हैः–

Activity Name	Sanctioned Project Cost	GBS	PMA Charges	GBS for PMA Charges	10% Counter Part fund from State
	(Rs Cr)	(Rs Cr)	(Rs Cr)	(Rs Cr)	(Rs Cr)
Smart Metering Works	1099.84	247.46	6.19	5.57	0.62

➢ Loss Reduction हेतु वित्तीय स्वीकृतिः

Activity Name	Sanctioned Date	Sanctioned Project Cost	GBS	10% Counter Part fund from State	PMA Charges	GBS for PMA Charges	10% Counter Part fund from State
		(Rs Cr)	(Rs Cr)	(Rs Cr)	(Rs Cr)	(Rs Cr)	(Rs Cr)
Loss Reduction Works	18.07.2022	1262.00	1135.80	126.20	18.93	17.04	1.89
IT/OT Works		164.00	147.60	16.40	2.46	2.21	0.25
LT Auxiliary item for DT SM works	14.01.2025	20.19	18.17	2.02	0.30	0.27	0.03
Total		**1446.19**	**1301.57**	**144.62**	**21.69**	**19.52**	**2.17**

क्रमशः.....4

➢ आर0डी0एस0एस0 के अन्तर्गत अन्य स्वीकृतियां:

i. **Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTG):** (पी0एम0–जनमन)

Activity Name	Sanctioned Date	Sanctioned Project Cost	GBS	10% Counter Part fund from State
		(Rs Cr)	(Rs Cr)	(Rs Cr)
Particular Vulnerable Tribal Group (PVTG) work under PM-Janman	05.10.2024	0.5916	0.53	0.06

ii. **Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTG) की भौतिक प्रगति:**

Sl. No.	District Name	Electrified PVTG HH (Nos.)
1	Dehradun	462
2	Haridwar	119
3	Nainital	81
4	Udham Singh Nagar	7
Total		**669**

- PVTG योजना के अन्तर्गत समस्त चिन्हित 669 नं0 लाभार्थियों (बुक्सा तथा राजी जनजाति) को निःशुल्क विद्युत संयोजन निर्गत कर संतृप्त किया जा चुका है।

iii. **DAJUGA** (धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान)

Activity Name	Sanctioned in MCM /Date	Sanctioned in MCM /Date	Sanctioned Project Cost	GBS	10% Counter Part fund from State
			(Rs Cr)	(Rs Cr)	(Rs Cr)
DA-JGUA (Dharti Aaba Janjatiya Gram Utkarsh Abhiyan)	47th MCM held on Dated 21.03.2025	02:10:RDSS:2021:I: UPCL/092119 Date: 26.03.2025	0.90	0.81	0.09

- DAJUGA योजना के अन्तर्गत कुल लक्ष्यान्वित 226 नं0 में से मार्च 2026 तक 169 नं0 हाउस होल्ड एवं पब्लिक इंस्टीटयूशन को निःशुल्क विद्युत संयोजन निर्गत किया गया है।

iv. **Border Out Post (BOPs):**

Activity Name	Sanctioned Date	Sanctioned Project Cost	GBS	10% Counter Part fund from State	PMA Charges	GBS for PMA Charges	10% Counter Part fund from State
		(Rs Cr)	(Rs Cr)	(Rs Cr)	(Rs Cr)	(Rs Cr)	(Rs Cr)
Border out Posts work	23.04.2025	327.51	294.76	32.75	4.91	4.42	0.49

क्रमशः.....5

- BOP योजना के अन्तर्गत 43 नग बोर्डर आउट पोस्ट जिनमें कि जनपद उत्तरकाशी 10, चमोली 16 एवं पिथौरागढ़ 17 पोस्ट तक विद्युतीकरण का कार्य किया जाना स्वीकृत है जिसके कार्यों के अनुबन्ध किये जा चुके है एवं कार्य प्रगति पर है।

v. **Vibrant Village Program (VVP):**

Activity Name	Sanctioned Date	Sanctioned Project Cost	GBS	10% Counter Part fund from State	PMA Charges	GBS for PMA Charges	10% Counter Part fund from State
		(Rs Cr)	(Rs Cr)	(Rs Cr)	(Rs Cr)	(Rs Cr)	(Rs Cr)
Vibrant Village Program work (VVP)	14.03.2024	12.89	11.60	1.29	0.19	0.17	0.02

- VVP योजना के अन्तर्गत 08 नग वाइब्रेंट विलेज जिनमें जनपद उत्तरकाशी को 01 एवं पिथौरागढ़ के 07 गांवों में विद्युतीकरण के कार्य का अनुबन्ध किया जा चुका है एवं कार्य प्रगति पर है। अनुबन्ध के आधार पर मार्च–2027 तक कार्य पूर्ण किए जाने हैं।

vi. **Undergrounding of HT/LT Line in Rishikesh with SCADA Automation in Ganga Corridor:**

Activity Name	Sanctioned Date	Sanctioned Project Cost	GBS	10% Counter Part fund from State	PMA Charges	GBS for PMA Charges	10% Counter Part fund from State
		(Rs Cr)	(Rs Cr)	(Rs Cr)	(Rs Cr)	(Rs Cr)	(Rs Cr)
Undergrounding of HT/LT Line in Rishikesh and SCADA	18.08.2025	547.83	493.05	54.78	8.22	7.39	0.83

- ऋषिकेश शहर में गंगा कोरिडोर के अन्तर्गत HT/LT लाइनों एवं SCADA Automation कार्यों हेतु अनुबन्ध किये जा चुके है। अनुबन्ध के अनुसार UG Work दिसम्बर 2026 तक पूर्ण किये जाने है तथा SCADA के कार्य दिसम्बर 2027 तक पूर्ण किए जाने है।

➢ **विशेष श्रेणी के राज्य:**

योजना के क्रियान्वयन में उत्तराखण्ड, सिक्किम, उत्तर पूर्वी राज्यों, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, अण्डमान निकोबार द्वीप समूह और लक्ष्यद्वीप के राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेश सहित विशेष श्रेणी के राज्यों के रूप में चिन्हित है। विशेष श्रेणी राज्यों को योजना के अन्तर्गत मानदंडों को पूरा करने पर Loss Reduction कार्यों की स्वीकृति के सापेक्ष 90 प्रतिशत धनराशि अनुदान के रूप में अनुमन्य होगी।

क्रमशः.....6

➢ नोडल एजेंसी

मै0 आर0ई0सी0, नई दिल्ली एवं मै0 पी0एफ0सी0, नई दिल्ली विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से योजना के क्रियान्वयन हेतु नोडल एजेंसी नामित है जिनके मध्य राज्यों में कार्यों के क्रियान्वयन हेतु बाँटा गया है। मै0 पी0एफ0सी0, नई दिल्ली उत्तराखण्ड राज्य हेतु नोडल एजेंसी नामित की गई हैं।

➢ पी0एम0ए0:-

योजना के क्रियान्वयन हेतु मै0 मेद्याज टैक्नों कॉन्सेप्ट प्रा0लि0, लखनऊ को पी0एम0ए0 (Project Management Agency) नियुक्त किया गया है।

➢ प्रगतिः-

- **स्मार्ट मीटरिंग योजना की प्रगति**

  योजना के अन्तर्गत वर्तमान में स्मार्ट मीटरिंग के लिए AMISP (Advance Metering Infrastructure Service Provider) की नियुक्ति कर गढवाल क्षेत्र में M/s Genus Power Solutions Pvt. Ltd., Rajasthan एवं कुमांऊ क्षेत्र में M/s Adani Energy Solutions Ltd., Gujrat के साथ 06, मार्च-2024 को अनुबन्ध किया गया है एवं कार्य प्रगति पर है। योजना के अन्तर्गत मीटरों की स्थापना के साथ-साथ AMISPs द्वारा ओ0एण्ड0एम0 का कार्य भी किया जाना है जिसकी कुल समयावधि माह जून-2034 तक है।

- **Loss Reduction Works की प्रगति**

  राज्य के अन्तर्गत Loss Reduction में किये जाने वाले कार्यों के अनुबन्ध हेतु समस्त मण्डलों के 12 पैकेजों के अनुबन्ध पश्चात् कार्य गतिमान है जिनका अनुबन्ध के आधार पर पूर्ण किया जाना जुलाई 2026 तक लक्ष्यान्वित था। दिनांक 30.09.2026 तक योजना के अन्तर्गत कार्यों की भौतिक प्रगति 70 प्रतिशत है यहां पर इंगित किया जाना आवश्यक है कि भारत सरकार द्वारा कार्यो को पूर्ण करने की समयावधि को मार्च 2028 तक विस्तार किया गया है किन्तु यू0पी0सी0एल0 इन कार्यों को मार्च 2027 से पूर्व पूर्ण किए जाने हेतु कटिबद्ध है।

- **आर0डी0एस0एस0 योजना के अन्तर्गत दिनांक 26.09.2026 तक भौतिक एवं वित्तीय प्रगतिः-**

  i. स्मार्ट मीटरिंग परियोजना में भौतिक एवं वित्तीय प्रगति क्रमशः 44.40 प्रतिशत 7.10 प्रतिशत है।

  ii. Loss Reduction (सभी घटकों की) कार्यों के सापेक्ष भौतिक एवं वित्तीय प्रगति क्रमशः 34.12 प्रतिशत एवं 31.59 प्रतिशत है।